exchange, i.o the tune of Rs. 400 crores per year to the Government; it is also one of the sources of excise income to the Government to the tune of Rs. 3,500 crores per annum. Naturally, the Government is not prepared to lose that and the farmer is not prepared to lose that but the diseases that the people of our country suffer from, the cause of these diseases has to be considered very seriously.

As "The Hindu", a prestigious newspaper, had commented in its editorial recently, it is a business without ethics, it is a business without social responsibility and just promoting ill-health and death, so the Gvoernment of India and the enlightened Members of this august body should seriously ponder over this important matter and initiate necessary preventive measures. This is my submission, Madam. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Shri Ahluwalia is not here.

SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY (West Bengal): I associate myself with the subject.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): The whole House would like to associate itself with the sentiments expressed by Dr. Radhakrishna Murty. We really endorse his views. *...(Interruptions)...*

RE: HIKE IN PETROL PRICES

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Madam, I would just take one minute of the precious time of the House. Yesterday the Finance Minister presented the Budget.We have come to know that there is a hike of one rupee per litre in the prices of petrol due to the cess which will be diverted for development of National Highways. The report which we are getting is that every petrol pump dealer is charging rupees four per litre as additional hike in petrol prices. The hon. Petroleum Minister is here.We would like to know as to what the exact position is. If the actual hike is only one rupee, then why are they charging rupees four per litre? If this is so, how are the ordinary people of this country going to bear this additional cost of rupees three which is being charged now? *...(Interruptions)...*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : मैंडम, लोक सभा के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी ने इसका स्पष्टीकरण दे दिया हैं । जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें कुछ मंत्रालय को समझने में गलती हो गई थी तो उसमें सुधार कर दिया गया हैं । अब फिर से जो बढ़ोत्तरी हुई हैं वह केवल एक रुपये की हुई हैं और बिक्री कर को मिला कर एक रुपये पन्द्रह पैसे के बीच बढ़ोत्तरी रहेगी । आपको कल सुबह अखबारों के माध्यम से **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : नहीं, लेकिन आप बताइये, अखबारों के बारे में तो मालूम हैं **...(व्यवधान)...**

SYED SIBTEY RAZI: I am very sorry, Madam. *...(Interruptions)...* The House should be informed. The Government should come out with the exact position in this regard. *...(Interruptions)...* Why should we know it through media? *...(Interruptions)...*

श्री संतोष कुमार गंगवार : सही रेट जो हुआ हैं आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी । **...(व्यवधान)...**

SYED SIBTEY RAZI: Why should we know it through media? *...(Interruptions)...* The House should be informed.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मंत्री जी, देखिए, आपने जो अभी कहा कि लोग सभा में मंत्री जी ने इसके बारे में कुछ खुलास किया हैं और आपने साथ में यह भी कहा कि कल आपको अखबारों के माध्यम से पता चलेगा तो यह बड़ी अजीब सी बात हैं । आप मंत्री परिषद् में मंत्री हैं । माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया हैं उसके बारे में आपको पाज़िटिवली कुछ कहना होगा ।

श्री संतोष कुमार गंगवार : पाज़िटिवली हमारा कहना यह हैं कि जोआप आपने अखबारों के माध्यम से चार रुपये का समाचार पढ़ा था उसका सुधार कर दिया गया हैं और बढ़ोत्तरी केवल एक रुपये ही रहेगी और माननीय सदस्यों को इसकी वजह से जो तकलीफ हुई हैं उसके लिए खेद हैं ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : ठीक हैं ।

सैयद सिब्ते रज़ी : मैडम, यह सवाल माननीय सदस्यों की तकलीफ कर नहीं हैं, मैं तो यह कहूंगा कि यह बहुत बड़ी लापरवाही हैं ऑन् द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मंत्री जी, जरा माननीय सदस्य को सुन लीजिएगा ।

SYED SIBTEY RAZI: This is a reckless and irresponsible thing on the part of the Government because lakhs of rupees have been taken away by the petrol pump dealers. How are you going to compensate the people who have purchased petrol today and have paid extra money due to your mistake? You are responsible for this. ...*(Interruptions)*... You should apologise to the nation, not to us. We are not the only people who have been put to inconvenience. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAGHAVJI (Madhya Pradesh); Newspapers are responsible for this. ... *(Interruptions)*...

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश) : मैडम ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : आप अगर वन बाय वन नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा ...(**व्यवधान**)

SYED SIBTEY RAZI: You say that some newspapers have done it. *(Interruptions)*... You are also saying that due to some miscalculation this has happened. I think if you are gong to apologise, you should apologise to the people of India because you are so irresponsible and you have not been able to convey the correct position as to what you wanted to do. Lakhs of rupees have gone into the pockets of petrol pump dealers because you were not able to convey the correct position of what you wanted to do. ...*(Interruptions)*...

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी : मैंडम, मैं आपके माध्यम से इनसे यह मालूम चाहता हूं कि जो पैसा आज और कल रात से पेट्रोल पंप पर लोगों का वसूल किया गया हैं क्या उसकी वापसी का कोई इंतजाम किया जाएगा ? अगर नहीं किया जाएगा तो यह पैसा किस मद में जाएगा ? जबकि बढ़ा सरकार के बजट से एक रुपया पन्द्रह पैसा था जैसा कि मंत्री जी कहते हैं । तो वह जो बाकी पैसा दो रुपये पैसठ पैसे का हैं क्या वह पर लिटर के हिसाब से जितना लिटर इस्तेमाल हुआ हैं क्या वह रिफंड होगा ? अगर नहीं होगा क्या this is not cheating ...(Interruptions)... They have cheated the people और इसके लिए जब कोई बयान कोई हैं, जब आप माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सुबह अखबारों के माध्यम से पता चला जाएगा, जिस पर आपने भी टिप्पणी कर दी, मैडम, कि अखबारों के माध्यम से ही यह बात मालूम हुई हैं यह जब बजे शाम के तो उसके बाद से आज तक मैं समझता हू कि करोड़ो-करोड़ रुपया सारे मुल्क का जनरल पब्लिक का चला गया होगा । ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हैं जैसे सिब्ते रज़ी साहब ने सदन के ध्यान में यह बात लाई हैं । क्योंकि कल रात से ही कई लोगों ने हमें यही कहा हैं कि बजट में तो मंत्री जी ने एलान किया था कि एक रुपए की बढ़ोत्तरी हुई हैं, लेकिन पेट्रोल पंपों पर हम को एक लीटर के ऊपर चार रुपए सक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं । मुम्बई भी कई लोगों ने यही शिकायत की और दोपहर को भी कुछ लोगों ने यही कहा । अब अचानक सिब्ते रज़ी साहब ने यह बात सदन के समाने रखी । अब मैं चाहूंगी कि मंत्रालय की ओर से अगर इस के प्रति कोई खेद व्यक्त किया जाता हैं और इस का सही स्वरूप रखा जाता हैं तो मुझे लगता हैं देश की जनता को भी लगेगा कि इस तरह की गलती हैं देश की जनता को भी लगेगा कि इस तरह की गलती की वजह से हमें आज एक रुपए की जगह तीन रुपए साढ़े तीन रुपए ज्यादा देने पड़े हैं ।

प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी एक्जैक्ट जानकारी ले लें कि एक ही रुपया बढ़ा हैं, एक रुपया पांच पैसे या एक रुपया दस पैसे बढ़ा हैं और आज सदन उठने से पहले यह बता दे । अब इस में 15 या 20 परसेंट बाद में एक्साइज ड्यूटी का इंक्रीज हुआ हैं । अभी मंत्री जी आप ने कहा कि यह एक रुपया या एक रुपया 15 पैसा होगा, वह अखबारों में आ जाएगा । यह ठीक नहीं हैं । यह सदन को पहले मालूम होना चाहिए और अखबारों में बाद में जाना चाहिए कि एक्रअल में वृद्धि क्या हैं ? दूसरे यह जो रुपया पेट्रोल पंप वालों के पास कल और आज आ गया हैं तो कल और आज ही में कई करोड़ रुपया उन के पास आ गए हैं ।

फिर उन को जो पेट्रोल दिया गया, वह किस भाव से दिया गया, पेट्रोल मिनिस्ट्री का तो उस में उतना ताल्लुक नहीं हैं, लेकिन यह रुपया कहां जाएगा ? ये रुपया पेट्रोल पंप वालो के पास न रहे हैं और वह गवर्नमेंअ के पास आ जाये । यह तो ठीक हैं कि वह हरेक का हिसाब-किताब होकर उसे वापिस तो नहीं जा सकेगा, मगर वह रुपया पब्लिक के ही काम में आना चाहिए, पब्लिक के लिए ही यूटिलाइज होना चाहिए और वह कहीं बीच में नहीं चला जाय, इस के लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, अगर मंत्री महोंदय इस बारे में भी जानकारी लेकर सदन उठने से पहले बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मल्होत्रा जी, अभी मंत्री जी ने कुछ कहते-कहते यह भी कह दिया कि मंत्री जी ने लोग सभा कि लिए वक्तव्य को सुधार लिया हैं और कल तक अखबारों के माध्यम से मालूम हो जाएगा । अब आप ने जो सुझाव दिया हैं, यह ठीक ही कहा हैं । मंत्री जी जाएं, इस की जांच-पड़ताल करें और शाम को सदन उठने से पहले कोई वक्तव्य निश्चित दे जिस की वजह से कल से आज तक आम जनता जो स्कूटरों, श्री व्हील्र्स और कारों के लिए पेट्रोल लेती हैं, उन्हें जो असुविधा हुई हैं, उस बारे में वह अपने वक्तव्य में खेद भी प्रकट करें ।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Madam, what are they going to do now?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : वह तो मंत्री जी ही बताएंगे ।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: Madam, they have collected excess amount becaues it comes under the provisons of the Essential Commodities Act they are liable to be prosecuted.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I think, let the Minister come and make a statement on the floor of the House. If there is any clarification to be sought on that statement from the Minister, you can do so.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: Madam, let them come out with all the things. Are they going to prosecute the people who have collected excess amount? *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Okay. Now, I think, I would like to take up the business of the Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 1997, for consideration.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Madam, 1 have a query.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): About what?

SHRI NILOTPAL BASU: About the Urea price. Madam, yesterday, it was announced that there will be an increase of Re. 1 per K.G on Urea. But now,we are told that there has been some statement in the other House by the hon. Agricultural Minister that it will be reduced. Now, I want a ruling on this. When the Budget has been placed, can any Minister *suo motu* announce in the House that there is a reduction? What is the legal position on this because there has been a statement? *...(Interruptions)...* What is the sanctity of the Budget? Can he actually do it? *...(Interruptions)...* I want a clarification on this.

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): Madam, now this has become a part of the Finance Bill. No Minister on the floor of the House can just declare and say that there has been a mistake. We were all listening to the hon. Finance Minister yesterday. He was very categorical while saying that there will be an increase of Re. 1 per K.G. in the price of Urea. *...(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, what is the sanctity of the Budget?

SHRIMATI KAMLA SINHA: Just one minute. This has become a part of the Finance Bill. .Now, another Minister— Agricultural Minister— says, "No", it is going to decrease.

This cannot be done in this way. There should be an amendment in the Finance Bill, and that should be brought in both the Houses. I do not think that any Minister has any right to make a correction in the Lower House and not in the Upper House. It should be done simultaneously in both the Houses. Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Shri Gurudas

Das Guptaji ...*(Interruptions)*... Just a minute. I will allow everybody one by one. If all of you get up at the same time, then it would be very difficult for me

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam, it is a matter of grave parliamentary impropriety. It is a matter of grave parliamentary impropriety. I hope that Members on all sides will kindly take note of it. It is not a question whether the Finance Minister made a mistake while reading out his well-prepared speech. It is also not a question whether the Government is going to amend it. A person can commit a mistake and the mistake can be amended. A Government can make a decision and the decision can also be changed. But, the point is if a change has to be made— whether the change was by mistake or deliberate— it can only be done in both the Houses simultaneously. Neither are we a second chamber nor are we a secondary chamber. This is a House of Elders, a House of States. Since morning we have been receiving telephone calls from Calcutta that people are charging exorbitant rates for petrol. But, we could not raise this matter because we had certain other important issues to raise. Now it is being said that the hon. Minister has made a statement in the Lower House to correct his position. Let him correct here also. If it is not corrected here, should the House take his delibeia-tion? I do not know ..*(Interruptions)*... If it is an amendment in the Finance Bill, then he has to take the permission of the House. If it is an amendment the House must permit the amendment; otherwise, it cannot be done *suo motu*. Therefore, it is a question of serious impropriety. And if the Agriculture Minister has said something, it only goes to indicate that the Ministers are working at random at cross purposes. It is a multi-dimentsional Government. The Government is not speaking in one voice. It only speaks of the serious weaknesses, of the incoherence, of the fragile and untendable character of the Government. That is for the Government to decide. That is not for me. If the credibility of the Government goes down because of the contradictory statements by the Ministers, it is for the Government to retrieve its credibility. It is for the Government to correct its mistake. But,, my point is that it is a question of grave parliamentary impropriety. You must call the Minister here to explain to the House what prevented him from coming to the House. Why did he make a unilateral statement in one House and sideline the other House?

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, my point is entirely different. My point is that the Budget was presented in both the Houses. Now, it is a question of correction. The rates of urea have been revised. The rates have been reduced by 50 paise per kg. It was announced *suo-motu* in Lok Sabha. I want to seek a clarification from the Government as well as from the Chair that as long as the Budget is before the House, is it not the property of the House? So, the Minister has to take the leave of the House to introduce a revision, if in their wisdom they thing so. So, it is not only improper, but it is totally against the constitutional procedure and conduct of the business of the House. So, would the Government clarify the position? Every now and then it is happening that the governance and the business of the House is being con ducted in a manner that is raising grave doubts on the functioning of the Govern ment itself. Government has to come out clearly on this issue as to what exactly they are trying to do..... *(Interrup tions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SAROJ KHAPARDE) You had made you point yesterday, Mr. Nilotpal Basu. No, Mr. Malhotraji.

प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा : मैडम, अगर आप बहस को आगे चला रही हैं तो बात दूसरी हैं क्योंकि अभी आपने एक डायरेक्टिव दिया था मिनिस्टर साहब को कि वे जाएं.....

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): The direction :

which I had given was on a different point. That was on petrol. Now they are raising about urea. So, the subject is different.

प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा : मैं उसी पर आ रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, फाइनेंस मिनिस्टर ने अगर वहां पर एक बजट रखा हैं तो उसमें चेंज भी तो फाइनेंस मिनिस्टर ही करेंगे न, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं । कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर उसके बारे में दूसरी स्टेटमेंट दे रहा हैं या नहीं, हमें मालूम नहीं हैं । उस हाऊस में क्या हुआ हैं, उस हाऊस में क्या बताया गया हैं, दोनों हाऊस में एक साथ बताया जाना जरूरी हैं, मै पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं और इस हाऊस को पता लगना चाहिए कि क्या चेंजिस हुई हैं और अगर चेंजिस हुई हैं,तो क्या दोनों मिनिस्टर्स ने कोई अलग-अलग बयान दिए हैं, वह भी पता लगे ? अभी तो कुछ मालूम ही नहीं हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी मिनिस्टर यहां पर हैं वे जाकर इस बात को देखें और पूरा पता करके इस हाऊस को पूरे कांफिडेंस में लिया जाना चाहिए, इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं । अगर सचमुच में कोई चीज़ बढ़कर के कम हुई हैं तो हाऊस को तो खुशी होनी चाहिए । इम्पोपराइटी की बात तो हो सकती हैं, परन्तु ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मल्होत्रा जी. आप जो बात कह रहे हैं, this is not your prerogative. This is the preogative of the Minister. आप अपनी बात कहिए बाकी मुझे जो चेयर से रूलिंग देनी हैं, मैं दे दूंगी । मुझे ऐसा लगता हैं कि जो आपने बात सदन के सामने कही हैं, वह ठीक कही हैं । जहां तक कि मैम्बर्स ने यूरिया के बारे में अपने विचारों को सदन के सामने रखा हैं, वह उनका अधिकार हैं और गुरूदास दासगुप्त जी ने बिल्कुल सही बात कही । that this is a second Chamber not a secondary Chamber. अगर कोई मंत्री इस तरह की बात करते हैं कि ओअर हाऊस में जाकर एक बयान दें और अपर हाऊस को उसकी जानकारी नहीं रहे तो इस तरीके की स्टेप मदरली ट्रीटमेंट पार्लियामेंट में नहीं चलती हैं । मेरी सरकार से अनुरोध रहेगा कि पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर यहां पर बैठे हुए हैं, माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार यहां पर व्यक्त किए हैं, उसकी वे टिप्पणी लें और टिप्पणी लेने के बाद वे संबंधित मंत्री से इसकी चर्चा करें और पूरे सदन को विश्वास में लेकर वे यहां पर इस तरीके से अपना एक बयान रखें ताकि मैम्बर्स के मन में जो भावना आई हैं कि इस तरह की ट्रीटमेंट जो हमारे सदन को मिल रही हैं, वह भावना उनकी खत्म करने की कोशिश करें ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, You kindly direct him to come.

श्री मंत्री (श्री सत्या नारायण जटिया) : वे गए हैं न पता लगाने के लिए ।

श्रीमती कमला सिन्हा : मैडम, आप सरकार को यह निर्देश दें कि वित्त मंत्री इस सदन में आएं और आकर दोनों, मामलों में स्थिति को स्पष्ट करें – पैट्रोल के मामले में भी यूरिया के मामले में भी क्योंकि बजट कल उन्होंने पेश किया, दूसरे किसी मंत्री ने नहीं पेश किया ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : कमला सिन्हा जी, असल में दोनों चीजें जो हैं वे फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही संबंधित हैं और इसीलिए मैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर को कहूंगी कि फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर आएं और यह जो देश की जनता के मन में दुविधा की स्थिति हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा हैं कि किसके प्राइसिस कम हुए किसके ज्याद हुए, इसका क्लोरिफ़िरकेशन अगर वे सदन के सामने दें तो मुझे लगता हैं कि ज्यादा अच्छा होगा और इस प्रकार की दुविधा की स्थिति में न आप रहेंगे और न देश की जनता रहेगी ।

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी : मैडम, ये बहुत अह्म मसले उठे हुए हैं ...(**व्यवधान**)...

प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा : पहले ही टाइम नहीं हैं ।

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी : टाइम की बात तो और हैं, सवाल यह हैं कि कल बजट पेश किया गया हैं । दोनों हाऊस अपने में इंडिपेंडेंड हैं, वहां जो कुछ किया गया, दोनों हाऊस को-रिलेटिड हैं, वहां जो कुछ किया गया वह यहां होना चाहिए अगर वह नहीं हुआ हैं अब तक तो वह यह हाऊस चलेगा कैसे ? ...(**व्यवधान**)... मैडम, एक प्वाइंट उठा हैं पेट्रोल का और एक साथी ने यूरिया का मामला उठाया । अगर इन दोनों प्वाइंट्स पर ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : गुफ़रान साहब, आपने शायद सुना नहीं कि मैंने यही डायरेक्शन्स निर्देश दियाहैं कि हमारे फ्राइनेंस मिनिस्टर यहां आएं और सदन के सामने अपना बयान रखें । बस बात खत्म हो गई ।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): We will now take up the Legislative Business. We will

take up further corrsftteration of the Payment of Gratuity (Amendment) Bill.

Shri Govindrao Adik. He is not here. Shri Thalavai Sundaram.

THE PAYMENT OF GRATUITY (AMENDMENT) BILL, 1997

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM (Tamil Nadu): Thank you, Madam Vice-Chairman, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the Payment of Gratuity (Amendment) Bill.

Madam, this is a very simple Bill. It is beneficial to the employees. Therefore, I welcome this Bill. In 1994, the amount was fixed at Rs. one lakh. Through this Bill, this ceiling is being raised to Rs. 3,50,000/-.

I would like to use this opportunity to bring to the notice of the hon. Minister one specific thing. 1 would like to invite the attention of the hon. Minister to sections 11 and 12 of the Payment of Gratuity Act, 1972. Section 11 says: 'No court shall take cognigance of any offence punishable under this Act, save on an application made by, or, under, the authority of the appropriate Government'. The other section, i.e. section 12, says: 'No suit or other legal proceedings shall lie against the controlling authority or any other person in respect of anything which is in good faith done, or, intended to be done, under this Act, rule or other made thereunder'.

Yesterday, Madam, we considered the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill. Our learned friend, Shri Dipankar Mukherjee, pointed out that more than 15,000 workers are not getting their provident fund and gratuity dues. As far as Tamil Nadu is concerned, more than 12,000 workers are not getting their gratuity amount.

Sometimes, there may be some dispute between the management and the employee. Because of the provisions contained in sections 11 and 12 of the Act. the court cannot interfere. In such a situation, when the workers' dues are not paid by the management, how are we going to settle the matter? I would like to know from the hon. Minister whether he is thinking of amending the Bill to take care of this aspect. As per the existing provisions, since the court cannot interfere, the workers would not be able to get a single paise from the management. Therefore, this point should be considered. This is one thing.

Secondly, Madam, some companies are deposting the amount in low interest-earning instruments. I would suggest to the hon. Minister to lay down some guidelines in this regard so that the amount is deposited in good and proper interest-earning instruments. Otherwise, there would be a heavy loss for the companies as well as the employees.

To sum up, firstly, there should be an amendment in regard to the court's jurisdiction to interfere. Otherwise, thousands of workers would continue to be denied their dues. Another thing is; how to channelies the gratuity amount. A number of people retire every year. We should see that the matter is settled, at least, one year before.

Thank you, Madam.

SHRI DRUPAD BORGOHAIN (Assam): Thank you, Madam, for allowing me to make certain points on this amending Bill.

Considering the objective of the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972, considering the old age security benefit deserved by the employees on retirement from service, and considering that his amendment, if accepted by the House, would render a better relief to the employees in the present-day situation of escalation of prices, I welcome the amendment to the said Act by the Government.

First of all, I would like to know about the implementation of the law. This amendment which enhances the gratuity ceiling is beneficial. There is no doubt about it. But the question is: for whom